

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोन:- 2386031, 2386032 फैक्स:- 0744-2386033

वर्ष: 50 संख्या: 184

प्रभात

कोटा, शनिवार 19 अप्रैल, 2025

कोटा/24/2012-14

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के लिये विदाई भोज की तैयारी आरंभ होने लगी है

इस घटनाक्रम से यह आकलन लगाया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में नए भाजपा अध्यक्ष का चयन पूरा हो जायेगा

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 अप्रैल। भाजपा-आरएसएस ने भाजपा-अध्यक्ष के चयन के अंतिम निर्णय की प्रक्रिया तेज कर दी है, क्योंकि यह मुद्दा लम्बे समय से खिंचता चला आ रहा है और इससे ऐसा संदेश जा रहा है कि पदमुक्त होने जा रहे पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के स्थानापन्न के मामले में संघ परिवार के अंदर कोई बड़ा मतभेद है।

सूत्रों का कहना है कि नड्डा के विदाई समारोहों की श्रंखला शुरू हो गई है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नये पार्टी अध्यक्ष की नियुक्ति चन्द रोज में ही हो जायेगी।

सूत्रों का कहना है कि आरएसएस के मन में कुछ महत्वपूर्ण चिन्ताएं हैं, जिनका समाधान नये पार्टी अध्यक्ष के चयन एवं नियुक्ति से पहले होना जरूरी है। आरएसएस इस पद के लिये एक ऐसा ताकतवर और दृढ़ नेता चाहती है, जो किसी के भी आगे झुके नहीं, बल्कि मुद्दों के मामले में दृढ़ रहे तथा कठोर निर्णय ले सके।

कई सवाल हैं, जैसे सितम्बर में 75 साल के हो जाने पर, नरेन्द्र मोदी पद-

- आरएसएस यह चाहता है कि नया अध्यक्ष ऐसा मजबूत व्यक्ति हो, जो सख्त निर्णय ले सके और किसी के दबाव में झुके नहीं।
- दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न संघ के समक्ष है कि क्या मोदी 75वां जन्मदिन मनाने के बाद रिटायर होंगे तथा उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी जगह कौन लेगा और देश के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की गद्दी पर कौन बैठेगा।
- आरएसएस इस बात से भी काफी चिंतित है कि भाजपा से जो बहुत से युवा पहली बार जुड़े हैं, क्या वे संघ की संस्कृति में अच्छी तरह समावेश हो गये हैं।
- भाजपा के बड़े नेता इस बात पर आश्वस्त हैं, पर फिर, भाजपा व संघ परिवार दोनों चाहते हैं कि आरएसएस का पुराना कार्यकर्ता, जो संघ की संस्कृति में डूबा हुआ है तथा ओतप्रोत है, वही पार्टी का नया अध्यक्ष होना चाहिये।
- इन मुद्दों पर मूल सहमति नहीं बन पाई है अभी तक तथा ये गतिरोध खत्म करने के लिये सभी प्रयासरत हैं।

त्याग के लिये सहमत होंगे या नहीं?

मोदी के सेवानिवृत्ति होने की स्थिति में, उनके स्थान पर प्रधानमंत्री कौन बनेगा?

देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा?

देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा?

लेकिन आरएसएस के समक्ष

सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा नई नस्ल के उन नेताओं का है, जो अन्य पार्टियों से भाजपा में लिये गये हैं, और क्या वे नेता संघ-संस्कृति के साथ एकाकार हो गये हैं।

भाजपा की संस्कृति से अपरिचित ऐसे नेताओं को लेकर आरएसएस के अंदर बहुत अधिक बेचैनी है।

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का

फोकस बूथ-लैवल कमेटियों तथा जमीनी कार्यकर्ताओं से सम्पर्क जैसी पार्टी की असली सम्पत्तियों पर है और उनका कहना है कि भाजपा नेताओं की नई खेप इसके प्रति सजग एवं इससे परिचित है तथा वह पार्टी को संभाल सकती है।

लेकिन भाजपा का कहना है कि यह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूनेस्को के ‘‘मैमरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर’’ में गीता, नाट्यशास्त्र शामिल

नयी दिल्ली, 18 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने दुर्लभ अभिलेखों की अपनी सूची, ‘‘मैमरी ऑफ द वर्ल्ड’’ रजिस्टर में गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को भी शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने

- प्रधानमंत्री ने इसे हर भारतीय के लिये गर्व की बात बताया। इस सूची में अब भारत के दर्ज अभिलेखों की संख्या 14 हो गई।

इसकी प्रशंसा की और इसे दुनिया भर में रह रहे भारतीयों के लिए गर्व की बात बताया। इसके साथ ही इस सूची में भारत के दर्ज प्राचीन अभिलेखों की संख्या 14 हो गयी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ‘भारत की सभ्यतागत विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने यूनेस्को के निर्णय के बारे में संस्कृति मंत्री शेखावत के एक पोस्ट पर टिप्पणी में, लिखा, समूचे विश्व में प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण। गीता और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लायसैंस नहीं है तो राजापार्क के रैस्त्रा बंद करो

जयपुर, 18 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम ग्रेटर को निर्देश दिए हैं कि याचिका में पक्षकार बनाए गए 9 रेस्त्रां के पास यदि लाइसैंस नहीं है तो उनका आगामी सुनवाई तक संचालन रोका जाए। चीफ जस्टिस एम.एम श्रीवास्तव और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश शालिनी श्रीवास्तव व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में बताया कि शहर में संचालित कई रेस्त्रां और अन्य प्रतिष्ठान नगर निगम की ओर से दिए जाने वाले

- हाई कोर्ट ने नगर निगम ग्रेटर को निर्देश दिये, अगली सुनवाई तक बिना लायसैंस वाले रैस्त्रां का संचालन रोकें।

लाइसैंस के बिना ही खाद्य सामग्री बेच रहे हैं। जिसके चलते आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस संबंध में नगर निगम की कई बार शिकायत भी दी गई, लेकिन अभी तक निगम प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता की ओर से शहर के राजा पार्क क्षेत्र में संचालित 9 रेस्त्रां संचालकों को पक्षकार भी बनाया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि यदि इन 9 रेस्त्रां के पास निगम का लाइसैंस नहीं है तो अंतरिम रूप से उनका संचालन रोका जाए।

उप मु.मंत्री एकनाथ शिंदे, अमित शाह से मिले, पर इससे उनकी कमज़ोरी ही जाहिर हुई

म्युनिसिपल चुनाव से पूर्व, एकनाथ शिंदे काफी हिले हुए हैं क्योंकि उन्हें शिव सेना के उद्भव ठाकरे खेमे व भाजपा गठबंधन के अन्य घटकों से एक साथ संघर्ष करना पड़ रहा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 अप्रैल। हाल ही में, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बीच हुई गोपनीय मीटिंग से राज्य में सत्तारुढ़ ‘‘महायुति’’ गठबंधन की दरारों के गहरी होने की व्यापक अटकलें लगाई जा रही है। ज्ञातव्य है कि राज्य के म्यूनिसिपल चुनाव होने में कुछ सप्ताह ही शेष हैं। तेरह अप्रैल को मुम्बई के सहयात्री गैस्ट हाउस में हुई इस मीटिंग ने गठबंधन की एकता को लेकर चिन्ताएं बढ़ा दी हैं। फन्डस तथा राजनैतिक पदों को लेकर पैदा हुई अन्दरूनी विवादों से सत्तारुढ़ गठबंधन के स्थायित्व के लिये खतरा पैदा हो गया है।

महायुति गठबंधन, जिसमें शिवसेना (शिन्दे गुट) भारतीय जनता पार्टी तथा नैशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी (एनसीपी-अजित पवार गुट) शामिल हैं, 2024 के हलचलपूर्ण विधानसभा

- भाजपा ने अप्रत्यक्ष संकेत दिया है कि वो घटकों के आपसी संघर्ष में एनसीपी (अजित पवार) के पक्ष में हैं। यह भाजपा का, महाराष्ट्र की राजनीति की दृष्टि से बुद्धिमतापूर्ण कदम है, पर, शिंदे के लिये खतरे की घंटी है।

- शिंदे ने मुम्बई में 13 अप्रेल को सहयाद्री गेस्ट हाउस में बात करके, शिव सेना को तोड़ने में अपनी भूमिका याद दिलाई तथा अमित शाह से हस्तक्षेप करने की दुहाई दी। मगर, शाह पर इस दुहाई का खास असर होता नहीं दिख रहा है, तो क्या महायुति गठबंधन टूट भी सकता है?

चुनावों के बाद सत्ता में आया था। इसका गठन 2022 में शिव सेना के नाटकीय रूप से टूटने के बाद हुआ था, जब शिन्दे ने उद्भव ठाकरे का नेतृत्व अख्तीकार कर दिया तथा महाविकास अघाड़ी सरकार को सत्ता से हटाने के लिये भाजपा से गठजोड़ कर लिया था। इस पार्टनरशिप ने मुख्यमंत्री देवेन्द्र

फडुनवीस की सत्ता में वापसी तो हो गई थी, लेकिन शिन्दे गुट का अपने मित्र दलों के साथ तालमेल नहीं हो पा रहा है और उनका असंतोष बढ़ता ही जा रहा है, और उनका यह तनाव शाह के साथ हाल ही हुई उनकी मीटिंग से खुलकर सामने आ गया है। सूत्रों का कहना है कि संसाधनों के आवंटन तथा राजनैतिक

महत्व से सम्बंधित शिकायतों के समाधान के लिये शिन्दे ने शाह का हस्तक्षेप की मांग की है। इस विवाद का मुख्य कारण राज्य के वित्तीय संसाधनों का वितरण है, जिस पर एन.सी.पी. नेता अजित पवार का नियंत्रण है। शिंदे ग्रुप का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है।

एक और विवादाम्यद मुद्दा रायगढ़ जिले के संरक्षक मंत्री का पद है, जो आर्थिक और चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। शाह के, एन.सी.पी. नेता सुनील तटकरे के घर जाने से इस धारणा को और बल मिला है कि भाजपा इस पद के लिए तटकरे को प्राथमिकता दे रही है, जिससे शिंदे गुट स्वयं को हाशिए पर महसूस कर रहा है और इसे लेकर गुट में नाएजगी बढ़ रही है। नगर निगम चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में ये मतभेद महंगे साबित हो सकते हैं। ये चुनाव महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में गठबंधन की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दो हजार से ऊपर के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी नहीं

नयी दिल्ली, 18 अप्रैल। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और ऐसे किसी भी प्रस्ताव की बात भ्रामक और निराधार है।

बयान में कहा गया है कि कुछ

- वित्त मंत्रालय ने कहा इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपकरणों (कार्ड जैसे माध्यमों) का उपयोग करके किए गए भुगतानों से संबंधित मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) जैसे शुल्कों पर ही जीएसटी लगाया जाता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) 30 दिसंबर 2019 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) को यूपीआई के माफित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बाइस नक्सलियों ने सामूहिक आत्म समर्पण किया

सुकमा, 18 अप्रैल। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 40.5 लाख रुपये के 12 इनामी माओवादी सहित 22 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष शस्त्रवार को सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वालों में नौ महिला नक्सली भी शामिल हैं। इन नक्सलियों ने एक साथ पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

- इन नक्सलियों में से 12 पर 40 लाख रुपये का इनाम था।

(सीआरपीएफ) के अफसरों के सामने सरेंडर किया है। इन पर कुल 40 लाख रुपये का इनाम घोषित है। ये सभी नक्सली माड़ डिवीजन (छत्तीसगढ़) और नुआपाड़ा डिवीजन (ओडिशा) में सक्रिय रहे हैं। आज एक साथ सरेंडर करने वाले नक्सलियों में एक दंपति भी शामिल है। इन पर आठ-आठ लाख रुपये का इनाम घोषित है। इनके सरेंडर को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका तीन सप्ताह में ही, जल्दी से जल्दी, भारत के साथ व्यापारिक समझौता फाइनल कर लेना चाहता है

अमेरिका का मकसद केवल ‘‘टैरिफ’’ में भारत के पक्ष में कुछ व्यवहारिक कमी करना ही नहीं है, बल्कि, चीन की एशिया व विश्व में व्यापारिक धाँस पर अंकुश लगाना है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 18 अप्रैल। तेजी से बदलते वैश्विक ट्रेड ड्य़ामा में भारत एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में उभरा है क्योंकि अमेरिका अपने अन्य मित्र देशों की तुलना में भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए जल्दबाजी में है। इसमें टैरिफ रेट के अलावा और भी बहुत कुछ दांव पर है। इस डील से इंडो पैसिफिक इकॉनमिक ऑर्डर में भारत की स्थिति पुनः परिभाषित हो सकती है और चीन के वैश्विक दबदब को नियंत्रित करने के लिए यू एस के नेतृत्व वाली रणनीति को प्रोत्साहित करेगा। पता चला है कि भारत, जापान

- अमेरिका चाहता है, भारत से ‘‘बायलेटरल’’ व्यापारिक समझौता करके पैसिफिक देशों (साउथ कोरिया, वियतनाम, ताईवान, आस्ट्रेलिया व जापान) से व्यापारिक अरैंजमेंट को फाइनल करे।

- उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। उन्होंने एक इन्टरव्यू में कहा कि भारत पर वैसे भी ‘‘टैरिफ की मार’’ नहीं पड़नी चाहिये, क्योंकि भारत तो ‘‘टैरिफ वॉर’’ के बहुत पहले से ही अमेरिका से ‘‘बायलेटरल’’ व्यापारिक समझौते की बात कर रहा था।

भारत का बहुत कुछ दांव पर लगा है। वॉशिंगटन के साथ कई महीनों से

चल रही उच्च स्तरीय वार्ता के बावजूद भारत को ट्रंप की नई टैरिफ लिस्ट में

शामिल किया गया और भारतीय सामान पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया। यह रेट दक्षिण कोरिया के समकक्ष है, पर वियतनाम व ताईवान से कुछ कम है। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक इंटरव्यू में बताया कि टैरिफ की धमकी से बहुत पहले से ही भारत द्विपक्षीय वार्ताएं कर रहा है। भारत उन देशों में नहीं था, जिन पर वास्तव में टैरिफ लगाने की जरूरत थी, क्योंकि हम पहले से ही द्विपक्षीय वार्ताएं कर रहे थे।’’

चीन के विपरीत, भारत ने शांत और व्यवहारिक रास्ता अपनाया। जहाँ चीन ने भी बदले में आक्रामक टैरिफ लगाए और निर्यात पर नियंत्रण किया, वहीं नई दिल्ली ने बैक चैनल डिप्लोमसी और

वार्ता का सहारा लिया। इसी बीच अमेरिका ने भारत के साथ डील को प्राथमिकता दी और अमेरिका, ब्रिटेन के साथ अपनी बहुप्रतीक्षित संधि से पहले भारत के साथ डील को फाइनल कर लेगा। यह तत्परता ट्रम्प प्रशासन की रणनीतिक प्राथमिकता को दर्शाती है, जिसमें वह अपने इंडोपैसिफिक सहयोगियों के साथ व्यापारिक समझौते करने की दिशा में काम कर रहा है।

नई दिल्ली के व्यापारिक वार्ताएं सिर्फ टैरिफ से छूट के लिए ही नहीं हैं, बल्कि इससे कहीं अधिक हैं। भारत जैनरिक दवाओं के निर्यात, आईटी सेवाओं और ई-कॉमर्स, जहाँ भारतीय (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●

⊕

● ● ● ● ●

CMYK